संख्या. ए-30012/03/2024- समन्वय

भारत सरकार

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

खुर्शीद लाल भवन,
जनपथ, नई दिल्ली,
दिनांक: 04.11.2024

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: माह सितम्बर, 2024 का मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश - तत्संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को सितम्बर, 2024 माह के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की गतिविधियों का मासिक सार इसके साथ परिचालित करने का निर्देश हुआ है।

<u>संलग्नक: यथोपरि</u>।

(राज कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23455303

सेवा में,

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य ।
2. भारत सरकार के सभी सचिव ।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के माननीय राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
6. भारत के माननीय उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली।
7. प्रधान सूचना अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रथम तल , शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:

i. माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, खुर्शीद लाल भवन, नई दिल्ली, के निजी सचिव

ii. सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय), खुर्शीद लाल भवन, नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।

iii. अपर महा निदेशक (CQCD), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, खुर्शीद लाल भवन, नई दिल्ली

iv. अपर महा निदेशक, CICD, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, खुर्शीद लाल भवन, नई दिल्ली।

v. उप महा निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, खुर्शीद लाल भवन, नई दिल्ली।

अन्य प्रतिलिपि :

डीआईआईडी, लेवल-3, पूर्वी ब्लॉक-10, आर.के. पुरम, नई दिल्ली को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर मासिक सारांश अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

<u>सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का माह सितंबर, 2024 के लिए मासिक सारांश</u>

1. मंत्रालय ने अखिल भारतीय ग्रामीण, शहरी, संयुक्त क्षेत्र के लिए **आधार 2012=100** पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के उप-समूहों/समूहों की कीमतों में उतार-चढ़ाव **सितंबर, 2024** (अनंतिम) के महीने के लिए और **अगस्त, 2024** (अंतिम) के लिए **14 अक्टूबर, 2024** को जारी किए। ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्र के लिए **सितंबर, 2024** (अनंतिम) के महीने के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) क्रमशः 5.87%, 5.05%, 5.49% की वार्षिक मुद्रास्फीति दर दर्शाते हुए 196.7, 191.4 और 194.2 थे। **अगस्त, 2024** के महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्र हेतु संबंधित मुद्रास्फीति दर (अंतिम) क्रमशः 4.16%, 3.14% और 3.65% थी।

2. ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्र के लिए **सितंबर, 2024** (अनंतिम) के महीने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) क्रमशः 203.0, 210.9 और 205.8 था। ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्र के लिए **सितंबर, 2024** (अनंतिम) के महीने के लिए सीएफपीआई के लिए अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर क्रमशः 9.08%, 9.56% और 9.24% थी। **अगस्त, 2024** के महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्र के लिए तदनुरूपी मुद्रास्फीति दर (अंतिम) क्रमशः 6.02%, 4.99% और 5.66% थी।

3. आधार वर्ष 2011-12 के साथ **अगस्त, 2024** (त्वरित अनुमान) महीने के लिए अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) **11 अक्टूबर, 2024** को जारी किया गया था और यह **145.6** था।

4. वाधवानी सेंटर फॉर गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन (डब्ल्यूजीडीटी) के सहयोग से मंत्रालय ने 2 सितंबर, 2024 को "उभरती प्रौद्योगिकियों" पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक परस्पर बातचीत का आयोजन किया। परस्पर बातचीत में प्रदान की गई प्रमुख अंतर्दृष्टि अंकरूपण, डिजिटलीकरण और डिजिटल परिवर्तन पर थी।

5. राज्य आय और संबंधित समुच्चय के संकलन के लिए राज्यों की क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु (i) अहमदाबाद, गुजरात में दिनांक 02.09.2024 से दिनांक 06.09.2024 के दौरान और (ii) अगरतला, त्रिपुरा में दिनांक 23.09.2024 से 27.09.2024 के दौरान राज्य आय और संबंधित समुच्चय के संकलन पर राज्य डीईएस अधिकारियों के लिए दो क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

6. आगामी उद्यम सर्वेक्षणों पर व्यापार संघों के साथ 12 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा.) के आगामी उद्यम सर्वेक्षणों नामतः वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई), वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (एएसयूएसई), आर्थिक जनगणना (ईसी), वार्षिक सेवा

क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (एएसएसएसई) और सीएपीईएक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यापार समूहों, संघों और व्यापार संगठनों के साथ सां.और कार्य.कार्या.मंत्रा. ने सहभागिता की।

7. राष्ट्रीय लेखों के प्रथम तिमाही अनुमानों पर चर्चा करने तथा अपने स्तर पर मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद और संबंधित समुच्चयों के निहितार्थ को समझने के लिए 13 सितंबर, 2024 को आरबीआई, मुंबई में एक बैठक आयोजित की गई।

8. व्यापार सांख्यिकी पर एक अनुवर्ती बैठक 18 सितंबर, 2024 को आयोजित की गई। इसका उद्देश्य व्यापार सांख्यिकी में सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार करने हेतु मुद्दों पर चर्चा करना था।

9. मंत्रालय 2025-26 में 8वीं आर्थिक गणना करना चाहता है। 8वीं आर्थिक गणना से संबंधित विभिन्न परिचालन और तकनीकी मामलों पर चर्चा करने के लिए 8वीं आर्थिक गणना की विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक 19 सितंबर 2024 को हुई, जिसकी अध्यक्षता सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पूर्व महानिदेशक डॉ. जी.सी. मन्ना ने की।

10. मंत्रालय की डेटा इनोवेशन (डीआई) लैब घटक क्षमता विकास योजना की शासी परिषद (जीसी) की पहली बैठक 18 सितंबर 2024 को हुई। शासी परिषद ने अभिनव समाधान की खोज के लिए समस्या विवरणों का अनुमोदन, शैक्षणिक और शोध संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

11. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षणों में गैर-प्रतिक्रिया के मुद्दों का समाधान करने के लिए, उच्च आय वर्ग / गेटेड सोसायटियों के साथ एक विचार-मंथन सत्र 20 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

12. एनएसएस की संचालन समिति की बैठक कैपेक्स सर्वेक्षण, 19वीं आईसीएलएस की संस्तुतियों पर आंतरिक अध्ययन, वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (एएसयूएसई) और वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2022-23 और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के मसौदा परिणामों की प्रस्तुति पर उद्यम सर्वेक्षणों और घरेलू सर्वेक्षणों के तकनीकी सलाहकार समूहों द्वारा की गई प्रमुख संस्तुतियों पर चर्चा के लिए 21 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

13. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर पूर्वानुमानकर्ताओं और अर्थशास्त्रियों के साथ 24 सितंबर, 2024 को मुंबई में पारस्परिक वार्तालाप हुआ। इस बातचीत में 40 से अधिक पूर्वानुमानकर्ता, सचिव (डीईए), मुख्य आर्थिक सलाहकार, पीएम के ईएसी सदस्य और अन्य वरिष्ठ हस्ताक्षरकर्ताओं ने भाग लिया।

14. हितधारकों की समझ बढ़ाने और नीति निर्माण तथा अनुसंधान के लिए पीएलएफएस डेटा की प्रभावी उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए 26 सितंबर, 2024 को पुणे में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) पर डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया।

15. निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के पूंजीगत व्यय निवेश धारणाओं पर अग्रगामी सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षकों की अखिल भारतीय कार्यशाला 26 सितंबर, 2024 को पुणे में आयोजित की गई थी, जिसमें निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के पूंजीगत व्यय निवेश धारणाओं पर अग्रगामी सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए सभी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

16. अर्थव्यवस्था, योजना और विकास मंत्रालय, कोट डी आइवर (आइवरी कोस्ट) सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने 23 सितंबर, 2024 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, यह जानना था कि भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली सांख्यिकी के क्षेत्र में मानदंडों और मानकों को कैसे बनाए रखती है।

17. मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में सुधारों पर संस्तुतियों के एक सेट के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे नीति आयोग, एनएससी, आरबीआई, डीईए, सीईए, ईएसी, पूर्व-सीएसआई आदि से पीएमओ के माध्यम से प्राप्त इनपुट/सुझावों के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की है, जिसे आठ लक्ष्यों में विभाजित किया गया है। संस्तुतियों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सचिव (सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा.) द्वारा लक्ष्यवार द्वि-मासिक समीक्षा की जा रही है। सभी लक्ष्यों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के दो दौर पूरे हो चुके हैं और, समीक्षा का तीसरा दौर सितंबर, 2024 के महीने में शुरू किया गया है।

18. मंत्रालय ने महीने के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन/प्रेस नोट जारी किए:
i. "एनवीस्टेट्स इंडिया 2024: पर्यावरण लेखा " शीर्षक से प्रकाशन का लगातार सातवां अंक 30 सितंबर 2024 को जारी किया गया, जिसमें ऊर्जा, महासागर, मिट्टी और जैव विविधता पर कुछ लेखा शामिल हैं।
ii. 25 सितंबर 2024 को 'भारत में पेरोल रिपोर्टिंग: एक रोजगार परिप्रेक्ष्य - जुलाई, 2024' पर प्रेस नोट।
iii. 23 सितंबर 2024 को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वार्षिक रिपोर्ट (2023-2024)।
iv. 30 सितंबर 2024 को वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) अंतिम परिणाम (2022-2023)।

19. सितंबर 2024 के 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली चालू केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए नवीनतम फ्लैश रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित मुख्य बिंदु थे:

चालू परियोजनाओं की कुल संख्या	1792
परियोजनाओं की मूल लागत	27,56,378.31 करोड़
परियोजनाओं की अनुमानित लागत	33,32,647.33 करोड़

परियोजनाओं की संख्या: निर्धारित समय से आगे	49
परियोजनाओं की संख्या: निर्धारित समय पर	529
समय से अधिक समय लेने वाली परियोजनाओं की संख्या	844
मूल लागत के संबंध में लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं की संख्या	459
समय और लागत दोनों में वृद्धि वाली परियोजनाओं की संख्या	291
माह के दौरान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की निगरानी सूची में जोड़ी गई/शामिल की गई नई परियोजनाओं की संख्या	21
पूर्ण होने की सूचना दी गई परियोजनाओं की संख्या	13
मार्च 2024 तक संचयी व्यय	रु. 15,88,917.69 करोड़
चालू माह के दौरान व्यय (सितंबर 2024)	रु. 26,438.11 करोड़
चालू वित्त वर्ष के दौरान सितंबर 2024 तक व्यय	रु. 1,64,706.51 करोड़
सितंबर 2024 तक संचयी व्यय	रु. 17,53,624.20 करोड़
मेगा परियोजनाओं की संख्या (1000 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली)	629
मेगा परियोजनाओं की मूल लागत	रु. 22,40,975.42 करोड़

20. अवसंरचना क्षेत्रों के निष्पादन पर नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-अगस्त वित्त वर्ष 24-25 में वित्तीय वर्ष 23-24 के इसी महीने की तुलना में सभी प्रासंगिक मापदंडों अर्थात् [विद्युत] विद्युत उत्पादन (+ 7.12%) [कोयला] लिग्नाइट उत्पादन सहित कोयला (+ 7.79%) [इस्पात] तैयार इस्पात का उत्पादन (+ 5.39%) [सीमेंट] सीमेंट उत्पादन (+ 0.85%) [उर्वरक] नाइट्रोजन, फॉस्फेट और यूरिया उत्पादन (+ 1.5%) [पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस] कच्चा तेल संसाधित (+ 1.41%) और प्राकृतिक गैस उत्पादन (+ 2.19%) [सड़कें] एनएचएआई द्वारा राजमार्गों का उन्नयन (+ 7.29%), [रेलवे] यात्री यातायात का संचालन (+ 5.76%) और राजस्व अर्जित करने वाला माल यातायात (+ 2.35%) [पोत परिवहन] प्रमुख बंदरगाहों पर कुल कार्गो का संचालन (+ 4.87%) और प्रमुख बंदरगाहों पर कोयले का संचालन (+ 4.13%) [नागर विमानन] अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात का संचालन (+ 12.42%) और घरेलू यात्री यातायात का संचालन(+ 6.17%) [नागर विमानन]हवाई अड्डों पर निर्यात कार्गो का संचालन(+ 20.39%) और हवाई अड्डों पर आयात कार्गो का संचालन (+ 19.54%) में सकारात्मक वृद्धि दर देखी गई है। कुछ मापदंडों अर्थात् (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) कच्चे तेल का उत्पादन (-1.7 प्रतिशत), राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा राजमार्गों का उन्नयन (-13.56 प्रतिशत) और [दूरसंचार] बेस ट्रांससीवर स्टेशनों सहित टावर (-92.74 प्रतिशत) में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

****